>

Title: Need to include farmers under centrally sponsored scheme MGNREGA for the development of agricultural activities in the country.

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): सभापति महोदय, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि भारतीय किसानों के लिए एक भी ऐसी योजना भारत सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है, जिसका किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुंचे। आज भारत में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि विकास योजनाओं को सीधे तौर पर किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि इसका सीधा-सीधा लाभ किसानों को मिल सके तथा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों के विकास हेतु उन्हें सीधे तौर पर मनरेगा योजना से जोड़ा जाना चाहिए।

मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर और दरभंगा जिलों में जो किसान खेती करते हैं, वहां का जलस्तर इतना नीचे तक चला गया है कि बोरिंग से पानी नहीं निकल रहा है, जिसके कारण वहां फसल सूख रही है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि स्पेशल स्कीम चलाकर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और उनकी सूखती हुई फसल को बचाने के लिए कम से कम माननीय सासंद की अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत में जो दो-दो स्टेट बोरिंग होता है, वह स्टेट बोरिंग एवं 20 चापाकल पेयजल के लिए प्रत्येक पंचायत में संस्थापित करवाने का कष्ट करें।

दूसरी बात यह है कि वहां की जो जनता और गरीब लोग हैं, वे पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि सारे चापाकल सूख गए हैं। पानी की भारी किल्लत हो गई है। एमएमएनपी के द्वारा भारत सरकार से जो चापाकल जाते हैं, प्रदेश सरकार के पास पहुंचने के बाद वह बंदरबाँट हो जाता है। आम जनता और गरीबों के बीच में नहीं जा पता है। दो-चार सौ में बिक जाता है। मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ माननीय सांसद की अनुसंशा पर ही चापाकल लगाने का आदेश यहां से दिया जाए। जिससे वह गरीब जनता तक पहुंच पाए। आप पूरे देश में देख लिजिए कि एमएमएनपी के तहत भारत सरकार, प्रदेश सरकार को जो पैसा देती है वह कहीं भी सही जगह पर नहीं लग पाता है। मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ कि माननीय सांसदों द्वारा अनुशंसित पत्र पर ही कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा चापाकल गड़वाया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।